लोकतंत्र की आत्मा है - संवाद

हरियाणा संवाद

पाक्षिक 16 -30 सितंबर 2021 www.haryanasamvad.gov.in अंक -26

"ईश्वर को देखना है तो प्रकृति को गौर से देखना और महसूस करना शुरू करें। इसके लिए पेड़ सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। : स्वामी परमहंस

सरकारी कामकाज के लिए समय सीमा निर्धारित

3

रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी

5

पैरालंपिक में छाया रहा हरियाणा

6

वैक्सीनेशन के संग जीत जाएंगे हम

आशंकित लहर से निपटने की तैयारी

विशेष प्रतिनिधि

राज्य में कोविड- 19 सीरो सर्वेक्षण के तीसरे दौर की शुरुआत हो चुकी है। सीरो सर्वे का पहला दौर अगस्त, 2020 में आयोजित किया गया था जिसमें कोविड-19 की व्यापकता 8 प्रतिशत थी। दूसरा दौर अक्टूबर, 2020 में आयोजित किया गया जिसमें संक्रमण की व्यापकता 14.8 प्रतिशत पाई गई थी। हालिया रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने का अनुमान है।

सीरो सर्वे में यह देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर कितने एंटीबॉडी बन चुके हैं और यह एंटीबॉडी किस प्रकार तैयार हुई। पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति के अंदर वैक्सीनेशन के अनुसार एंटीबॉडी तैयार हुई है या कोरोना के संक्रमण के बाद एंटीबॉडी विकसित हुई है। सर्वे में यह भी पता लगाया जाएगा कि व्यक्ति के अंदर कोवैक्सीन या कोविशील्ड इत्यादि वैक्सीन के पहली व दूसरी डोज लेने के बाद कितने प्रतिशत एंटीबॉडी तैयार हुई है।

यह सीरो सर्वे में 36,520 सैंपल लिए जाएंगे, पिछले सर्वे में 18500 के लगभग सैंपल लिए गए थे। इसमें 6 से 9 साल तक के लगभग 3600 बच्चों, 10 से 17 साल की आयु तक के 11 हजार और 18 साल से ऊपर के 22 हजार लोगों को शामिल किया जा रहा है। इस सर्वे में कुल सेम्पल का 60 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र व 40 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के लोगों का अनुपात होगा। सर्वे को करने के लिए लगभग 2200 मेडिकल स्टाफ को लगाया गया है। इसी रिपोर्ट के आधार पर आशंकित तीसरी लहर के लिए मापदंड बनाए जा सकेंगे।

एसीएस राजीव अरोड़ा के मुताबिक प्रदेश में 18 साल से ऊपर की 1.90 करोड़ जनसंख्या पात्र लोगों की है जिनमें से लगभग 1.25 करोड लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वैक्सीनेशन ही एकमात्र कोरोना संक्रमण से बचाव का कवच है। वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

घरों में ही मनाएं त्यौहार

स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि त्यौहारों का सीजन आ रहा है। आशंका संक्रमण बढ़ने की है। सभी परिवारों से आग्रह है कि वे त्यौहार घरों में ही रहकर ही मनाएं। उन्होंने बताया कि पीएम केयर फण्ड से 42 आक्सीजन प्लांट हरियाणा में लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा, 139 आक्सीजन प्लांट के लिए टेंडर लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी 50 बिस्तर से ऊपर के सरकारी अस्पतालों में पीएसए प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए हैं तथा 50 बिस्तर से ऊपर के सभी निजी अस्पतालों को भी अपने यहां पीएसए प्लांट लगाने के लिए कहा गया है, यदि निजी अस्पताल अपने यहां आक्सीजन प्लांट नहीं लगाते हैं तो उनका लाईसेंस कैंसिल किया जाएगा।

सीसीटीएनएस सिस्टम में हरियाणा नंबर वन

क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम प्रणाली में शत-प्रतिशत अंकों के साथ हरियाणा प्रदेश ने देशभर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह दूसरी बार है जब हरियाणा पुलिस ने इस प्रणाली के तहत 100 प्रतिशत अंकों के साथ देश में पहला स्थान हासिल किया है। हिमाचल ने 99.6 प्रतिशत अंकों के साथ दूसरा और कर्नाटक ने 99.3 प्रतिशत अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। गुजरात 99 प्रतिशत स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहा।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार और आईटी) एएस चावला ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय के प्रगति डैशबोर्ड पर एकीकृत अपराध और आपराधिक नेटवर्किंग और प्रणालियों की समीक्षा तथा निगरानी नियमित अंतराल पर प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मापदंडों जैसे राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों की कनेक्टिविटी, पुलिस स्टेशनों में कंप्यूटर सिस्टम की उपलब्धता, नागरिक सेवाओं का निपटान, पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण, सिस्टम पर पुलिस स्टेशनों द्वारा कार्य करना, पुराने डेटा की डिजिटाइजेशन और सिस्टम में उपलब्धता, गिरफ्तार और लापता व्यक्तियों की तस्वीरों का सीसीटीएनएस में इन्द्राज और सिस्टम से तैयार चालानों को अदालतों में जमा करना आदि के लिए की जाती है।

स्वच्छ भारत मिशन में सहयोग की दरकार

मनोज प्रभाकर

दस हजार व उससे अधिक की आबादी वाले गांवों में सीवरेज व गलियों के निर्माण का कार्य चल रहा है। इनके अलावा अन्य गांवों में भी विभिन्न विकास कार्य गति पर हैं। बहुत से गांवों के खेतों में चार करम के कच्चे रास्तों को पक्का कर दिया गया है, कुछ का किया जा रहा है। तालाबों का जीर्णोद्धार भी हो रहा है। ये कार्य कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से आम जनजीवन कुछ समय के लिए प्रभावित होता है।

ग्राम पंचायतों की अनुपस्थिति में संबंधित विभाग इन कार्यों को अंजाम देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर देखा जा रहा है कि कुछेक गांवों में ग्रामीण वजह बेवजह इन कार्यों में सहयोग की भावना नहीं रखते जिसकी वजह से विकास कार्य बाधित होते हैं और ग्रामवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

गांवों की सीवरेज प्रणाली का निर्माण सहज नहीं है। कार्य हो रहा होता है तो प्रभावशाली लोग उसे अपने ढंग से कराना चाहते हैं जिसके चलते व्यवस्था बिगड़ जाती है। अनेक गांव ऐसे हैं जहां के जोहड़ तालाबों पर अवैध कब्जे हैं। इन स्थिति में उन तालाबों का जीर्णोद्धार भी इतना सहज नहीं है। स्थानीय प्रशासन को काफी जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है। कुछेक ग्रामीणों के थोड़े से लालच व जिद् की वजह से पूरी योजना प्रभावित होती है। कार्य अधर में लटकते हैं तो परेशान होते ग्रामीण व्यवस्था को कोसने लगते हैं।

राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के सभी गांव स्वच्छ एवं सुंदर हों। बहुत से गांवों में ग्राम पंचायतें जागरूक रही हैं, खासकर युवा प्रतिनिधियों ने न केवल विकास कार्यों में सहयोग दिया है बल्कि खुद आगे बढ़कर विकास कार्य भी कराए हैं। मनोहरलाल सरकार-एक में शुरू की गई आदर्श गांव स्टार योजना का अनेक पंचायत प्रतिनिधियों ने फायदा उठाया। बहुत से युवा जनप्रतिनिधि तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने गांवों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया और हरे भरे सुंदर पार्क भी बनवाए।

हालांकि पूरे प्रदेश में पढ़ी-लिखी पंचायतों का गठन हुआ था लेकिन कुछेक रूढ़ीवादी विचारधारा के लोगों की वजह से विकास कार्यों में व्यवधान आए। अपनी 'नाक' की वजह से वे यह भूल गए कि अब नए जमाने का दौर है, यह सबके लिए जरूरी है। विकास में ही उनका सम्मान है, गांव का गौरव है। विकास से न केवल आज सवंरता है बल्कि भविष्य भी सहज हो जाता है। इसलिए विकास कार्यों में हर किसी ग्रामीण की सकारात्मक सोच व सहभागिता जरुरी है। शासन प्रशासन से कंधे से कंधा मिलाकर चलना समय की मांग है।

'जन भागीदारी से बनाएं गावों और शहरों को स्वच्छ'

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' अभियान की तरह 'स्वच्छ भारत मिशन' उनकी प्राथमिकता है। इसलिए जनभागीदारी के साथ प्रदेश के हर गांव और शहर को स्वच्छ एवं सुन्दर बनाया जाए। स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार की तरफ से दिए जाने वाले फण्ड का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें। इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय हो। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण केवल उन्हीं स्थानों पर करवाया जाए जहां पर आवश्यकता हो और इसकी संस्तुति रिपोर्ट की समीक्षा की जरूरत हो तो वह भी करवाई जाए।

संपादकीय

खेती में तो पिछड़ गया बड़ा भाई

कृषि-उत्पादन के मामले में हरियाणा ने अपने 'बड़े भाई' पंजाब को पछाड़ दिया है। इसका मुख्य कारण है कृषि संबंधी योजनाओं के मामले में हरियाणा की विशिष्ट पहलकदमियां। इसमें कोई संदेह नहीं कि वैसे दोनों राज्यों हरियाणा व पंजाब का देश को खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में शीर्षस्थ योगदान है लेकिन अब इस योगदान में हरियाणा काफी आगे है।

कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यद्यपि पंजाब का कृषि क्षेत्र हरियाणा से अधिक है लेकिन इस मामले में ठोस फैसले हरियाणा ने ज्यादा लिए हैं। पिछले सात वर्षों की अवधि में 11 फ़सलों और 21 फलों एवं सब्जियों का न्यूनतम मूल्य लागू करने में हरियाणा, पंजाब से कहीं आगे निकल गया है।

फसलों का विविधिकरण, 'फसल बीमा योजना' पर गंभीरता से अमल, भावांतर भरपाई योजना, फसलों का पूरी गंभीरता से पंजीकरण आदि के आधार पर हरियाणा अपने पड़ोसी प्रदेश से कहीं आगे जा चुका है।

हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्र 44212 वर्ग किलोमीटर है जबकि पंजाब का क्षेत्र 50362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी तरह से उपजाऊ धरती भी हरियाणा में पंजाब से कम है। वहां 42 लाख हैक्टेयर पर कृषि उत्पादन होता है जबकि हरियाणा में 37.41 लाख हैक्टेयर भूमि पर खेती होती है लेकिन कृषि-विकास की दर हरियाणा में 6.3 प्रतिशत रही है जबकि पंजाब में यह दर मात्र 2.1 प्रतिशत रही है।

गन्ना-उत्पादकों के लिए भी हरियाणा में 11 चीनी मिलें हैं और सबमें काम चल रहा है जबकि पंजाब में मिलों की संख्या तो 15 है लेकिन काम सिर्फ नौ में चल पा रहा है। आधा दर्जन ठप्प हैं।

हरियाणा अपने बड़े भाई पंजाब की अपेक्षा गेहूं, जौ, चना, सूरजमुखी, सरसों, धान, मूंग, मक्की, कपास-नरमा आदि फसलों की खरीद, घोषित न्यूनतम दरों में शत-प्रतिशत रूप में कर रहा है। वैसे भी भावांतर भरपाई योजना के तहत 21 प्रकार के फसल व सब्जियां पूर्ण मदद के दायरे में हैं, जबकि पंजाब में ऐसी कोई योजना नहीं है।

हरियाणा ने 81 मंडियों को ई-नैम (एनएएम) पोर्टल से जोड़ा, जबकि पंजाब में ऐसे पोर्टल से केवल 37 मंडियां ही जुड़ी हैं। पंजाब की 61 के मुकाबले में हरियाणा ने 76 प्रयोगशालाएं स्थापित कर दी हैं ताकि मिट्टी व सिंचाई जल का परीक्षण हो सके और फसलों की बिजाई उसी रिपोर्ट के आधार पर हो।

हरियाणा ने आढ़तियों को भी अपने खर्च पर, 10 लाख का बीमा दिया है जबकि पंजाब में ऐसी कोई योजना नहीं। 'ड्रिप सिंचाई' योजनाओं के लिए भी हरियाणा में 85 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है इसके साथ ही साथ 'पशुधन क्रेडिट कार्ड' योजना के तहत भी 58 हज़ार कार्ड जारी हो चुके हैं। हरियाणा में लगभग 17 लाख किसानों के 'फ़सल बीमा' के तहत चार हज़ार करोड़ रुपए की राशि मिली है जबकि पंजाब ने अभी तक यह योजना आरंभ ही नहीं की।

- डा चंद्र त्रिखा

चालू वित्त वर्ष के अंत तक राज्य में राशन के 500 डिपुओं को 'ग्राहक सेवा केंद्र' में बदला जाएगा। बहरहाल प्रदेश के पांच जिलों में चार बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर डिपुओं के माध्यम से सस्ती दरों पर आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। करनाल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर, पंचकूला जिला में अभी तक 63 दुकानों के साथ डाबर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, मैरिको लिमिटेड, कोका-कोला कंपनी, एल्प्रो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जोड़ा गया था। सफलता के बाद अब योजना राज्य को सभी 22 जिलों में शुरू किया जाएगा।

विभागीय मंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा दो जिलों, करनाल और सिरसा में पायलट के तौर पर सात डिपुओं को बैंकिंग प्रोजेक्ट के साथ जोड़ने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से टाइअप किया गया था। बैंक द्वारा इन डिपो-होल्डरों को वित्तीय लेन-देन का प्रशिक्षण दिया गया। आठ सप्ताह की अवधि में इन डिपुओं के माध्यम से जुलाई, 2021 के दौरान 24.40 लाख रुपए तथा अगस्त मास में लगभग 34.50 लाख रुपए का वित्तीय लेन-देन हुआ है।

ज्ञात रहे कि हरियाणा सरकार ने करीब आठ सप्ताह पहले 'आत्मनिर्भर हरियाणा' अभियान के तहत डिपो-होल्डरों के माध्यम से ब्रांडिड एफएमसीजी कंपनियों (फास्ट-मुविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी) का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की पायलट शुरूआत की थी। सात डिपो-होल्डरों के माध्यम से एसबीआई बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ देने की भी शुरूआत की गई, जिसके बदले में उनको कमीशन प्राप्त हुआ।

गांवों में वाजिब दर पर मिलेगा सामान

दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में एक इको-सिस्टम बनाना है ताकि गांवों के गरीब लोगों को राशन डिपो अथवा उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के माध्यम से बहुराष्ट्रीय एफएमसीजी कंपनियां, स्वयं सहायता समूह और अन्य विनिर्माण कंपनियां द्वारा प्रमाणित आवश्यक वस्तुएं वाजिब दर पर उपलब्ध करवाई जा सकें। इस योजना से जहां राज्य में आय और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों को मजबूती भी मिलेगी।

-संवाद ब्यूरो

सरल है वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना

राज्य में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्तियों के नाम सूची में शामिल करने की प्रक्रिया सरल है। वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के नए मामलों की स्वीकृति की अधिकतम समय सीमा 60 दिन निर्धारित है। केवल वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4430 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया जबकि अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 3241 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

आवेदक को नजदीक के नागरिक सेवा केन्द्र (सीएससी) या अंत्योदय केन्द्र जाकर अपने दस्तावेज अपलोड करवाने होते हैं। उसके बाद उसे सत्यापन के लिए केवल एक बार निर्धारित तिथि को संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जाना पड़ता है। यदि सत्यापन के दौरान दस्तावेज सही पाये जाते हैं तो उसका आवेदन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्वीकृत कर लिया जाता है।

वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 2740340 है जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता के लाभपात्रों की संख्या 1668067 है। वर्तमान में 18 अगस्त, 2021 तक 3400.01 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

जिन योजनाओं के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है उनमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, दिव्यांगजन पेंशन, विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता योजना, बोना भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना, स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता तथा कश्मीरी विस्थापित परिवारों को भी वित्तीय सहायता योजना शामिल है।

उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2015 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1000 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए मासिक किया गया जो वर्ष 2016 में 1600 रुपये, 2017 में 1800 रुपए, 2018 में 2000 रुपए, 2020 में 2250 रुपये तथा वर्तमान में पहली अप्रैल, 2021 इसे बढ़ाकर 2500 रुपए प्रतिमास किया गया है।

सलाहकार संपादक : डा. चंद्र त्रिखा
सह संपादक : मनोज प्रभाकर
संपादकीय टीम : संगीता शर्मा, सुरेंद्र मलिक
संपादन सहायक : सुरेंद्र बांसल
चित्रांकन एवं डिज़ाइन : गुरप्रीत सिंह
डिजिटल सपोर्ट : विकास डांगी

स्मार्ट मीटर लगवाएं, बिजली बिल में छूट पाएं

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम देश की अग्रणी वितरण कंपनियों में से एक है, जिसने मीटर रीडर्स की आवश्यकता के बिना वास्तविक समय मीटररीडिंग और स्टीक बिलिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने पर स्मार्ट मीटरिंग परियोजना शुरू की है। अब उपभोक्ता अपने वास्तविक समय मीटररीडिंग, दैनिक वास्तविक खपत की निगरानी कर सकते हैं और प्लेस्टोर और आईओएस पर उपलब्ध डिस्कॉम वेब पोर्टल या ''यूएचबीवीएन स्मार्ट मीटर'' मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करके ऑनलाइन भुगतान और अन्य सेवाओं के लिए अनुरोध कर सकते हैं। आसान ऑनलाइन रिचार्ज के साथ स्मार्ट मीटर में प्री-पेड सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें उपयोगकर्ता की खपत के अनुसार प्रीपेड बैलेंस को दैनिक आधार पर अपडेट किया जाता है। प्रीपेडबिलिंग को बढ़ावा देने के लिए, डिस्कॉम प्रीपेड उपभोक्ताओं को बिजली की बिक्री पर 5 प्रतिशत की छूट भी दे रहा है जो किसानों और किरायेदारों दोनों के लिए फायदेमंद है।

बिजली निगम के मुताबिक निगम द्वारा पहले चरण में पानीपत, करनाल और पंचकूला शहरों को चिन्हित किया गया है, जहां लगभग 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इन शहरों में लगभग 1.7 लाख स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और वर्तमान में पंचकूला के सेक्टर-2, 9 व 11, करनाल के मान कॉलोनी, आनंद विहार, कुंजपुरा, डीसी कॉलोनी, चार चमन व भुशाली तथा पानीपत के हरि नगर और भगत नगर में स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में स्मार्टमीटर लगाने के दौरान बिजली आपूर्ति को प्रभावित होने से बचाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और प्रभावित क्षेत्रों की पूर्व सूचना उक्त क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।

यूएचबीवीएन राज्य के उपभोक्ताओं को डिजिटल माध्यम से निर्बाध बिजली आपूर्ति, गुणवत्ता और पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है और उपभोक्ताओं को वैश्विक कोरोना महामारी की अवधि के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए इस स्मार्ट मीटर योजना का लाभ उठाने के लिए यूएचबीवीएन स्मार्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड करने का आग्रह करता है। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1912/18001801550 पर संपर्क कर सकते हैं।

हरियाणा में निवेश एवं रोज़गार बढ़ाने को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। एटीएल, फ्लिपकार्ट, मारुति जैसी बड़ी कंपनियों के बाद अब ई-कॉमर्स कंपनी 'अमेजन इंडिया' ने हरियाणा में अपने भंडारण नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के किसानों को गन्ने के भाव में 12 रुपए की बढ़ोतरी कर 362 रुपए प्रति क्विंटल देने का निर्णय लिया है। जोकि न केवल पंजाब से अधिक है, बल्कि पूरे देश में सर्वाधिक हो गया है।

सरकारी कामकाज के लिए समय सीमा निर्धारित

प्रदेश में एक सितंबर से 'राइट टू सर्विस एक्ट' लागू हो गया। मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने गत दिनों हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बनाये गए ऑटो अपील सॉफ्टवेयर 'आस' का लोकार्पण किया।

राजकीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को उसके घर-द्वार पर सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पहुंचाने के मकसद से यह सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। यह सरकारी सेवाओं की समयबद्ध तरीके से डिलीवरी में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी या कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा के अंदर काम नहीं करता, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेवा डिलीवरी में कोताही बरतने पर आयोग द्वारा तय की गई सजा पर सख्ती से अमल होना चाहिए। लेकिन जो अधिकारी और कर्मचारी समय से पहले काम कर देते हैं उन्हें रिवार्ड भी मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी सुशासन दिवस को लगभग 4 महीने बाकी हैं, इस दौरान हर कर्मचारी का मूल्यांकन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस समय 31 विभागों के 38 संगठनों की 546 अधिसूचित सेवाओं में से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जबकि 269 सेवाएं ऑफलाइन प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रशासकीय सचिवों को निर्देश दिए कि बाकी सेवाओं को भी जल्द से जल्द ऑनलाइन किया जाए।

सीएम विंडो से बचा समय व पैसा

मौजूदा सरकार ने सीएम विंडो लॉन्च करके आम आदमी को घर बैठे शिकायत दर्ज करवाने का अधिकार दिया है। अब तक इस पर लगभग 9 लाख शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं, जिनमें से सवा आठ लाख शिकायतों पर कार्रवाई की गई है। इस तरह देखा जाए तो हर रोज तकरीबन 400 लोगों को अपने छोटे-बड़े कामों के लिए चंडीगढ़ आना पड़ता था। अंत्योदय सरल पोर्टल, वैब हैलरिस, मेरी फसल-मेरा ब्यौरा जैसी अनूठी पहलों से लोगों का जीवन सुगम हुआ है।

ई-ऑफिस सिस्टम पर नंबर वन रहा झज्जर

झज्जर के डीसी श्याम लाल पूनिया ने बताया कि हरियाणा सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट ई-आफिस सिस्टम को सफल क्रियान्वित करने में झज्जर जिला प्रशासन प्रदेश भर में फिर से अग्रणी रहा है। अगस्त माह के चारों सप्ताह में झज्जर जिला ऑवर आल 8.9 स्कोर बोर्ड के साथ नंबर वन पर बना हुआ है।

सभी विभागाध्यक्षों व कर्मचारियों के सांझे प्रयास से मिली सफलता पर जिला प्रशासन टीम को बधाई देते हुए डीसी ने कहा कि अब झज्जर जिला के सभी विभाग पेपरलेस वर्किंग की अपेक्षा ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़ते हुए सरकारी सेवाएं आमजन तक पहुंचाने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। डिजिटल ई-आफिस सिस्टम में बैच-3 में डीआईपीआरओ कार्यालय 30.3 स्कोर बोर्ड के साथ जिला में अव्वल है जबकि बैच-2 में पशुपालन विभाग 24.7 स्कोर बोर्ड के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर रहा है।

डीसी पूनिया ने बताया कि नंबर वन की रैंकिंग निरंतर बनी रहे इसके लिए सभी विभाग ई-ऑफिस सिस्टम को लागू करते हुए कार्यालय की फाइल को मूव करवा रहे हैं जोकि प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के मद्देनजर सार्थक कदम है। सभी विभागाध्यक्ष ई-ऑफिस सिस्टम से जुड़कर कार्यालय की फाइल को डिजिटल माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। झज्जर जिला में बैच 0 से लेकर बैच 3 तक सभी विभागों की फाइल अब ई-आफिस सिस्टम से चल रही हैं।

डीसी श्याम लाल पूनिया ने बताया कि झज्जर जिला के सभी विभाग अब सरकारी कार्यों से संबंधित फाइल की फिजिकल मूवमेंट खत्म करते हुए केवल ई-ऑफिस सिस्टम पर ऑनलाइन फाइल को मूव कर रहे हैं। ई-ऑफिस प्रणाली पर फाइल की मूवमेंट से सरकारी कार्यालयों के कामकाज में पारदर्शिता आ रही है।

-संवाद ब्यूरो

शिक्षा है सर्वांगीण विकास का माध्यम: राज्यपाल

हरियाणा राजभवन में प्रदेशभर के निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं कुलसचिवों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय के अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षा मंत्री कंवरपाल और हरियाणा उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर बीके कुठियाला भी उपस्थित रहे।

राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के साथ-साथ सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षाविदों की अहम भूमिका होती है। वे शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए काम करें। शिक्षा ही सर्वांगीण विकास का माध्यम है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दूरदर्शी सोच के तहत तैयार की गई है। इस नीति से आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य साकार होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति में शिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका होगी।

राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को वर्तमान और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। यह हर्ष का विषय है कि हरियाणा सरकार इस नीति को 2025 तक पूरी तरह लागू कर देगी। 2025 तक शिक्षा नीति को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है।

शिक्षा से ही मिटेगी गरीबी

राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा से ही गरीबी मिटाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि संस्थानों की कमी के कारण बहुत से ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समाज के गरीब परिवारों के विद्यार्थी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छात्रवृत्ति आदि अनेक प्रावधान इन वर्गों के लिए हैं लेकिन अभी भी इन वंचित वर्गों के लिए बहुत कुछ करने की जरुरत है। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित शिक्षाविदों से आह्वान किया कि निजी विश्वविद्यालयों को न केवल ऐसे गरीब छात्रों को दाखिला देना चाहिए बल्कि उनके समग्र विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए।

-संवाद ब्यूरो

मॉडल बनते संस्कृति स्कूल

विद्यार्थियों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अब परिवार पहचान पत्र के अन्तर्गत सत्यापित अति गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन स्कूलों की निरंतर प्रगति के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड में जाकर स्कूलों का दौरा करने और हर माह इन स्कूलों की समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलों के वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसडीएम, डीडीपीओ, तहसीलदार एक-एक मॉडल संस्कृति स्कूल को गोद लेने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों की प्रगति को देखते हुए स्कूलों की संख्या बढ़ाने की मांग आने लगी है इसलिए अधिकारी व्यवहार्यता देखते हुए स्कूलों की संख्या बढ़ाने की दिशा में कार्य करें।

माध्यमिक शिक्षा के निदेशक एवं स्कूल शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री जे गणेशन ने बताया कि मुख्यमंत्री के बजट भाषण के दौरान राज्य के प्रत्येक खण्ड में सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी ताकि विद्यार्थियों को निजी स्कूलों के समान गुणवतापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। वर्तमान में राज्य में 137 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और 1418 मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूल चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में बच्चों की संख्या 27.90 प्रतिशत और मॉडल संस्कृति प्राथमिक स्कूलों में 16.73 प्रतिशत बढ़ी है।

हिंदी का विकल्प साथ साथ दें: सीएम

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निहित है कि राष्ट्रीय और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाए इसलिए इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिंदी माध्यम में भी शिक्षा ग्रहण करने का विकल्प विद्यार्थियों को दिया जाए। शिक्षा की गुणवत्ता पर निरंतर सुधार किया जाना चाहिए।

हरियाणा सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और व्यापक पर्यटन नीति बनाने और हरियाणा टूरिज्म के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाने के उद्देश्य से एक पेशेवर एजेंसी को नियुक्त करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने सिविल सचिवालय में डिजिटल सूचना पट्ट और आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आजादी के संघर्ष में हरियाणा के योगदान पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

पानी की बचत के साथ खर्च भी होगा कम

किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से कम पानी में फसलों का अधिक उत्पादन कर सकते हैं, जिससे पानी की बचत के साथ-साथ फसलों की सिंचाई पर होने वाले खर्च को भी कम किया जा सकता है। सूक्ष्म सिंचाई व काडा के मुख्य अभियंता विजेंद्र सिंह नारा ने बताया की प्रदेश के मुख्यमंत्री व कृषि मंत्री के निर्देश पर सरकार की ओर से किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के लिए और अधिक सुगम बनाने के लिए विभाग ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिस पर किसान यह प्रणाली अपनाने के लिए पंजीकरण कर सकते है।

उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेन्द्र सिंह व प्रशासक मिकाडा पंकज के निर्देशानुसार सिंचाई विभाग व सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के अधिकारी सरकार द्वारा तय लक्ष्य के अनुसार किसानों को अधिक से अधिक जागरूक करके सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से जोड़ा जाए। सूक्ष्म सिंचाई के लिए तालाब, सोलर पंप, मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप का निर्माण व स्थापित करवाना सुनिश्चित कर रहे है।

उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ किसान व्यक्तिगत या कम से कम दो या अधिक किसानों के समूह के रूप में ले सकते है। व्यक्तिगत रूप में किसानों को वाटर टैंक के निर्माण पर 70 प्रतिशत, सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तथा मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसी प्रकार किसानों के समूह को वाटर टैंक के निर्माण पर 85 प्रतिशत, सोलर पंप पर 75 प्रतिशत तथा मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप पर 85 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि वाटर टैंक की खुदाई पूरी होने पर सब्सिडी का 20 प्रतिशत, वाटर टैंक का निर्माण पूरा होने पर 40 प्रतिशत तथा लाभान्वित क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना पर 40 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सूक्ष्म सिंचाई में प्रयोग होने वाले ऑन फार्म पौन्ड के लिए जमीन हिस्सेदार जमीदारों को उपलब्ध करानी होगी और अनुमानित 25 एकड़ सूक्ष्म सिंचाई के लिए दो कनाल ज़मीन की उपलब्धता करानी होगी। इस योजना के तहत चैनल निर्माण व पुनः निर्माण के लिए खर्च की 99 प्रतिशत राशि सरकार द्वारा वहन की जाएगी बशर्ते चैनल के हिस्सेदार अपने हिस्से की एक प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए तैयार हो। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वैबसाइट www.cadaharyana.nic.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है।

घीया का भाव कम था तो बर्फी बनाकर बेचना शुरू कर दिया

संगीता शर्मा

कोरोना काल में हर किसी की नौकरी व बिजनेस प्रभावित हुआ। मगर इसका फ़ायदा एक यह हुआ है कि जो लोग गांव को छोड़कर शहर में अपने काम-धंधे में व्यस्त थे वह गांव की ओर वापिस लौट आए हैं। रेवाड़ी के पावटी गांव के सूर्यदेव ने घीये की खेती के साथ-साथ घीया की बर्फी बनाकर नई पहल की है।

सूर्यदेव ने छह महीने पहले ही हरियाणा सरकार के सहयोग से पावटी किसान उत्पादक संगठन का गठन किया है और वह समूह के निदेशक हैं। इसमें 18 साल से 55 साल के 25-30 किसान शामिल हैं जो कि सब्ज़ियों की जैविक खेती करते हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को समूह में शामिल होने के फ़ायदें के बारे में बताते हैं और उन्हें बागवानी विभाग, हरियाणा द्वारा किसानों को दी जा रही रियायतों का लाभ पहुंचाते हैं।

सूर्यदेव 15 एकड़ में घीया, दो एकड़ में करेला, दो एकड़ में तोरी, पांच एकड़ में गाजर, एक एकड़ में धनिया की जैविक खेती कर रहे हैं। अब मैथी की बुआई भी शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनके गांव में मीठा पानी है, इसलिए सब्ज़ियों की पैदावार बंपर होती है। आठ-नौ एकड़ में चेचरे भाई प्याज की खेती कर रहे हैं।

सूर्यदेव ने मुताबिक बावल के एसडीएम संजीव कुमार ने परामर्श दिया कि घीया के दाम कम हैं तो कुछ नया कर सकते हो। आप इसकी बर्फी बनाकर बेच सकते हो। यहां से मिले आइडिये को मैंने प्रयोग में लाया और 15 किलो घीये की बर्फी बनाकर उपहार दी। अब वह पावटी किसान उत्पादक संगठन के बॉक्स व बैग तैयार करके बर्फी बनवाएंगे और बाज़ार में बेचेंगे। उन्होंने बताया कि जन्माष्टमी के अवसर पर 65 किलो बर्फी बनाई थी और 60 किलो ऑर्डर पर बिकी। उनका कहना है कि आगे त्योहार का सीजन शुरू हो रहा है और मिठाई की मांग बढ़ने वाली है। नवरात्रि, दशहरा व दीवाली को देखते हुए अधिक बर्फी बनवाएंगे। इसकी कीमत 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से तय की है।

उन्होंने बताया कि उनके गांव में जैविक खेती होती है और जिसके कारण कोरोना महामारी यहां प्रभावित नहीं रही। उनका कहना है कि अच्छा खान-पान, स्वच्छ पर्यावरण और दूध-दही व घी के सेवन ने हमें बीमारी से बचाया। इससे हमारी इम्युनिटी अधिक मजबूत हुई है।

दूसरे राज्य में बेचना आसान हुआ

सूर्यदेव ने बताया कि इस समय मंडी में घीया पांच-छह रुपए प्रति किलो थोक रेट में बिक रहा है, जबकि कोई किसान बताया रहा था कि अहमदाबाद में 30-35 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसलिए उन्होंने अहमदाबाद की मंडी में स्वयं जाकर घीया की कीमत का जायजा लिया, लेकिन वहां भी अब दाम कम हो गए हैं। इसलिए अब वह हिमाचल की मंडी में अच्छे दाम मिलने पर वहां अपना घीया सप्लाई करेंगे। वह कहते है कि अब किसानों के लिए दूसरे राज्यों की मंडियों में सब्ज़ियां बेचने में आसानी हो गई है। जहां उनकी फसल के दाम उच्च होते हैं वहां बेचकर अधिक मुनाफ़ा कमा सकते हैं।

बाजरे की नई किस्म रोग प्रतिरोधक

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की उन्नत किस्में अब न केवल हरियाणा बल्कि देश के अन्य प्रदेशों में भी अपना परचम लहराएंगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तकनीकी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हुए दक्षिण भारत की तीन प्रमुख कंपनियों से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं।

समझौते के तहत विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बाजरे की किस्मों एचएचबी 67 संशोधित, एचएचबी 299 व एचएचबी 311 का बीज तैयार कर कंपनियां किसानों तक पहुंचाएंगी ताकि किसानों को उन्नत किस्मों का विश्वसनीय बीज मिल सके और उनकी पैदावार में इजाफा हो सके।

ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद कंपनी विश्वविद्यालय को लाइसेंस फीस अदा करेगी जिसके तहत उसे बीज का उत्पादन व विपणन करने का अधिकार प्राप्त होगा। इसके बाद किसानों को भी उन्नत किस्मों का बीज मिल सकेगा।

विश्वविद्यालय प्रवक्ता के मुताबिक एचएचबी 67(संशोधित) संकर किस्म में बायो टैक्नोलाजी विधि द्वारा जोगिया प्रतिरोधी जीन डाले गए हैं। एचएचबी 299 व एचएचबी 311 अधिक लौह युक्त(73-83 पी.पी.एम.)संकर बाजरा की किस्में हैं। इनके सिट्टे शंक्वाकार व मध्यम लंबे होते हैं। एचएचबी 299 किस्म 80-82 दिनों में जबकि एचएचबी 311 किस्म 75-80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अच्छा रख रखाव करने पर एचएचबी 299 व एचएचबी 311 क्रमशः 49.0 व 45.0 मनप्रति एकड़ तक पैदावार देने की क्षमता रखती हैं। ये किस्में जोगिया रोगरोधी हैं।

-संवाद ब्यूरो

सभी जिलों में अगले एक वर्ष भर 'आयुष आपके द्वार' महोत्सव में लोगों को लगभग 2,00,000 औषधीय पौधे वितरित किए जाएंगे। राज्य औषधीय पादप बोर्ड हरियाणा, आयुष विभाग, वन विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई।

हरियाणा भवन में 'इंटरनेशनल हरियाणा एजूकेशन सोसायटी' का शुभारंभ करते हुए सीएम मनोहरलाल ने कहा कि विदेश सहयोग विभाग के जरिए सरकार हरियाणा के युवाओं की विदेशों में पढ़ने व नौकरी करने के सपने को साकार करेगी।

झज्जर में आक्सीजन प्लांट

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने झज्जर जिलावासियों को विकास परियोजनाओं के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर ऑक्सीवन व ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करते हुए करीब 21.50 करोड़ रुपये की मनोहर सौगात दी है। झज्जर जिला के लोगों ने शिक्षक दिवस पर मिली सौगात का स्वागत करते हुए उनका अभिवादन किया।

मुख्यमंत्री ने झज्जर जिला में गांव समसपुर माजरा में साढ़े 18 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीवन का शुभारंभ किया। इसके अलावा, उन्होंने गांव शाहपुर मलिक में पांच एकड़ में रेवाड़ी खेड़ा में साढ़े चार एकड़ क्षेत्र में तथा गांव तलाव में अढ़ाई एकड़ में विकसित किए गए ऑक्सीवन का भी शुभारंभ किया। ये ऑक्सीवन झज्जर में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम साबित होंगे। मुख्यमंत्री ने समसपुर माजरा गांव में स्थित ऑक्सीवन में पौधारोपण भी किया।

कोरोना महामारी जैसी आपदा में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावी रूप से सुनिश्चित रहे इसके लिए मुख्यमंत्री ने पीएम केयर फंड से झज्जर जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट जिलावासियों को समर्पित किया। साथ ही गांव सिलानी केशो में स्थित चौधरी रणबीर सिंह राजकीय इंजीनियरिंग कालेज में 9.17 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित ब्वायज हॉस्टल, बेरी में 4.19 करोड़ रुपए से नवनिर्मित 33 केवी सब स्टेशन, लडरावण में 4.9 करोड़ रुपए से बने 33 केवी सब स्टेशन व सौलधा गांव में 3.89 करोड़ रुपए से बने 33 केवी सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया।

-संवाद ब्यूरो

रबी फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी

केंद्र सरकार ने मौजूदा फसल वर्ष के लिए गेहूं और सरसों समेत 6 रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफे का ऐलान किया है। गेहूं की एमएसपी 40 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इजाफे के बाद 2,015 रुपए प्रति क्विंटल की न्यूनतम कीमत पर गेहूं की खरीद होगी। इसके अलावा सरसों की एमएसपी 400 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 5,050 रुपए कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई में कैबिनेट कमिटी ऑन इकॉनमिक अफेयर्स की बैठक में यह फैसला लिया गया है।

जौ की एमएसपी 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। चने की कीमत 130 रुपए बढ़ाकर 5,230 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। मसूर की एमएसपी 400 रुपए बढ़ाने के बाद 5,500 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। कुसुम की एमएसपी 114 रुपए बढ़ाकर 5,441 रुपए प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है।

एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से फसल की खरीद करती है। इस समय सरकार खरीफ और रबी सीजन के 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है। रबी फसलों की बुआई अक्टूबर में खरीफ फसल की कटाई के तुरंत बाद होती है। गेहूं और सरसों रबी सीजन के दो मुख्य फसल हैं।

अटल भूजल योजना से होगी भूजल सुरक्षा

अटल भूजल योजना का लक्ष्य राज्य में आगामी पांच वर्षों के दौरान भूजल की कमी को 50 प्रतिशत तक दूर करना है। इस योजना के तहत हरियाणा के कुल 14 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें 36 भू-जल दबाव वाले ब्लॉक के साथ कुल 1669 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने यह जानकारी पंचकूला में हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण (एचडब्लूआरए) और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा हरियाणा में अटल भू-जल योजना पर राज्यस्तरीय कार्यशाला के आयोजन के दौरान दी। इस कार्यशाला का आयोजन अटल भूजल योजना से सम्बंधित विभिन्न विभागों और जिला कार्यान्वयन भागीदारों (डीआईपी) के संवेदीकरण करने के लिए किया गया था।

जल सुरक्षा योजना होगी तैयार

देवेंद्र सिंह ने बताया कि अटल भू-जल योजना केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा समर्थित और हरियाणा सरकार द्वारा कार्यान्वित एक सहभागी भू-जल प्रबंधन योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में भूजल संसाधनों का हाइड्रोजियोलॉजिकल डेटा नेटवर्क बनाना और राज्य में भूजल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सामुदायिक संस्था का निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत सामुदायिक लामबंदी और जागरूकता गतिविधियों के साथ-साथ हितधारकों का क्षमता निर्माण भी किया जाएगा। इस योजना के प्रारंभ में प्रत्येक गांव की जल सुरक्षा योजना तैयार की जाएगी और अगले चार वर्षों में इसे लागू किया जाएगा।

ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर ध्यान

देवेन्द्र सिंह ने घटते भू-जल स्तर की दिशा में काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों पर प्रकाश डालते हुए सभी नागरिकों को भू-जल तालिका का वास्तविक डेटा उपलब्ध करवाने के लिए अपील की ताकि घटते भू-जल स्तर को सुधारने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उन्होंने भू-जल प्रबन्धन से संबंधित डिसिजन सपोर्ट टूल्स को लेकर रणनीति सांझा की। उन्होंने कहा कि भू-जल को लेकर हमें सामुदायिक आधारित संस्थानों को मजबूत करने के साथ-साथ पानी के सही इस्तेमाल और ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर भी ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि अटल जल योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को वित्त प्रदान करती है तथा राज्य सरकारें इसे आगे कार्यान्वित स्तर जैसे कि जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायतों और लाभार्थियों तक वितरित करती हैं। उन्होंने 'मेरा पानी-मेरी विरासत योजना' पर जोर देते हुए कहा कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार धान की फसल छोडकर दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को 7 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर प्रोत्साहन राशि दे रही है। इसके तहत राज्य सरकार ने फसल विविधिकरण को बढ़ावा देने के लिए फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सुनिश्चित किया है।

फसल विविधिकरण के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश में 2030 तक बागवानी क्षेत्र को बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए 11 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं व तीन अन्य इस वर्ष के अंत तक भिवानी, हिसार व मेवात जिला में बनाए जा रहे हैं।

बागवानी फसलों की आसानी से बिक्री व उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में एक हजार किसान उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। अब तक 600 किसान उत्पादक समूह बनाए गए हैं। इन समूहों द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पेक हाउस बनाए जाएंगे, जिनके माध्यम से किसान अपने फल व सब्जियों को बेचने में सक्षम होंगे।

फलों व सब्जियों की ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए प्रदेश के 227 किसान उत्पादक समूह पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं। इनके माध्यम से प्रदेश के बाहर भी फल व सब्जियां बेची जाएंगी। फल व सब्जियों के शीत भंडारण के लिए कोल्ड स्टोर लगाने पर एक किसान के लिए 35 प्रतिशत व एफ.पी.ओ के लिए 80 से 90 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान किया गया है।

आम, अमरूद व सिट्रस फलों के बाग लगाने पर प्रति एकड़ 5100 रुपए से लेकर एक लाख 21 हजार रूपये तक का अनुदान दिया जा रहा है। ताकि किसानों का रूझान अधिक से अधिक बागवानी फसलों की ओर बढ़े, और उनको कम लगात में अधिक मुनाफा हो।

कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कि 'भावान्तर भरपाई योजना' में 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए हैं। इसी दिशा में 'मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना' भी शुरू की है जिसके तहत फसल की प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई की जाएगी।

हरियाणा सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लैब-अटैंडेंटस के लिए भी ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दी है। इससे स्कूल शिक्षा विभाग के कार्य-प्रदर्शन में भी सुधार होगा।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के व्यावसायिक स्थलों की नीलामी के मामले में पारदर्शिता बरतने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसके लिए पंजीकरण आरंभ कर दिया गया है।

पैरालंपिक में भी हरियाणा की धूम

टोक्यो पैरालंपिक में देश के लिए 19 पदक हासिल करने में हरियाणा के खिलाड़ियों का भरपूर योगदान रहा है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, दो रजत और दो कांस्य पदक हासिल करके कुल छह पदक लेकर देश का नाम रोशन किया है। राज्य सरकार ने इन खिलाड़ियों के मान-सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्हें नकद पुरस्कार व नौकरी देकर नवाज़ा जा रहा है।

पैरालंपिक में स्वर्णिम पताका फहराने वाले सुमित अंतिल का अभिनंदन करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रदेश के हर युवा-जवान-किसान-खिलाड़ी के साथ है, जिनके उत्थान में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। हरियाणा को खेलों के हब के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं, आगामी तीन वर्षों में प्रदेश के युवाओं को सरकार बड़ी संख्या में रोजगार देगी। जिसमें अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। खेवड़ा गांव के तत्वावधान में डीपीएस स्कूल के सभागार में पैरालंपियन सुमित अंतिल का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया।

सुमित अंतिल ने भाला फैंक में स्वर्ण पदक जीता तो 50 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक तथा सिंहराज ने निशानेबाजी में रजत पदक जीतकर हरियाणा के साथ-साथ भारत का नाम भी विश्व में रोशन किया है। कैथल के हरविंदर ने आर्चरी में कांस्य पदक जीता। खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा है कि यह जीत देश का मान बढ़ाने वाली है।

भाविना पटेल को 31 लाख रुपए

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि टेबल टेनिस के महिला एकल क्लास 4 वर्ग में रजत पदक जीतने वाली भाविना पटेल को भारतीय टेबल टेनिस फेडरेशन की ओर से 31 लाख रुपए की राशि दी जाएगी।उन्होंने कहा कि भाविना पटेल ने व्हीलचेयर पर बैठकर टेबल टेनिस के खेल में जो दमखम दिखाया है, उसने साबित कर दिया है कि अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी निःशक्तता व्यक्ति को लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती।

खेलों के क्षेत्र में हरियाणा मॉडल

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा का खेल मॉडल आज पूरे देश में नज़ीर बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा के खिलाड़ियों के पदकों की संख्या देखकर दूसरे प्रदेश भी हरियाणा पर रिसर्च कर रहे हैं। इसी मॉडल को समझने के लिए गुजरात की एक टीम हरियाणा में 15 दिन के दौरे पर आ रही है।

मुख्यमंत्री झज्जर जिला के गांव खुड्डन में ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान बजरंग पूनिया के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने खुड्डन गांव की ओर से रखी गई सभी मांगों के पूरा करवाने की घोषणा की जिस पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। पहलवान बजरंग पूनिया हरियाणा सरकार और गांव वालों से सम्मान पाकर अभिभूत हो गए। सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि पहलवान बजरंग पूनिया ने पूरे विश्व में भारत और हरियाणा का नाम रोशन किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में 500 खेल नर्सरियों के लक्ष्य को अब आगे बढ़ाकर 1,000 तक पहुंचाने की योजना है जिसके तहत स्कूली स्तर पर ही खिलाड़ियों की पौध तैयार होगी। आने वाले वक्त में खेलो इंडिया का आयोजन भी प्रदेश कर रहा है जिसमें 15,000 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे।

सम्मान समारोह में पहलवान बजरंग पूनिया के कोच द्रोणाचार्य अवार्डी सतपाल पहलवान, रामफल मान व वीरेंद्र आर्य को गुरु के रूप में सम्मान स्वरूप सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की गई। साथ ही झज्जर जिला में स्थित सभी खेल स्टेडियम में एक-एक कोच, माली अथवा चौकीदार तथा घास काटने की मशीन देने के निर्देश खेल निदेशक को दिए।

2024 में गोल्ड मेडल रहेगा लक्ष्य

कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 में वे स्वर्ण पदक लाने का लक्ष्य सामने रखकर अभ्यास में अभी से जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पैतृक गांव में जो उन्हें सम्मानित किया है उसका आभार वे पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण जीतकर आप लोगों का मान दुनिया में बढ़ा कर उतारेंगे।

-संवाद ब्यूरो

खेलो हरियाणा में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हर संभव खेल सुविधा देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है और प्रदेश की खेल नीति को देश में सबसे अच्छा माना जाता है। खिलाड़ियों को अच्छे खेल मैदान, आकर्षक इनाम राशि, डाइट की राशि में बढ़ोतरी के साथ ही अच्छे प्रशिक्षक भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसी के बदौलत हरियाणा के खिलाड़ी राष्ट्रीय, एशियाई, ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों में अपना सिक्का जमा रहे हैं। प्रतिभावान खिलाड़ियों को तैयार करने की कड़ी में प्रदेश के छह जिलों में 27 अगस्त से 29 अगस्त तक 'खेलो हरियाणा' खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

'खेलो इंडिया' में हरियाणा को मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो फरवरी 2022 में 'खेलो इंडिया' प्रतियोगिताएं पंचकूला में करवाई जाएंगी। इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए प्रदेश के छह जिलों में करीब 10 हजार खिलाड़ियों के लिए खेलो हरियाणा आयोजन किया गया है। इन खेलों से खेलो इंडिया के लिए 18 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ी (लड़के व लड़कियों) को तैयार किया जा रहा है।

भिवानी के ऋषभ, फतेहाबाद की तन्नू

ओवरऑल चैंपियन

बॉक्सिंग में लड़कों के वर्ग में भिवानी के ऋषभ व लड़कियों के वर्ग में फतेहाबाद की तन्नू ओवरआल चैंपियन रहे। इनमें लड़कों के वर्ग में पानीपत के लक्ष्य, फरीदाबाद के कर्ण, रोहतक के चमन तथा भिवानी के ऋषभ 'ऑल ओवर चैंपियन', लड़कियों के वर्ग में करनाल की तमन्ना, जींद की मुस्कान, रोहतक की हिमांशी तथा फतेहाबाद की तन्नू 'ऑल ओवर चैंपियन' रही।

शाहबाद मारकंडा के हाकी खेल प्रागंण में 'खेलो हरियाणा' की राज्य स्तरीय हाकी प्रतियोगिता के समापन समारोह के दौरान सरदार संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहली बार खेलो हरियाणा जैसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली हाकी की टीम को दो लाख, दूसरे स्थान आने वाली टीम को 1.50 लाख तथा तीसरे स्थान पर आने वाली टीम को एक लाख रुपए की राशि दी गई है। इस राशि को सीधा खिलाड़ियों के बैंक खाते में जमा करवाया जाएगा। इस दौरान खेलमंत्री ने हाकी की महिला व पुरुष विजेता टीमों को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में कुरुक्षेत्र की टीम प्रथम, हिसार दूसरे व सोनीपत तीसरे स्थान पर रही। पुरुषों वर्ग में जींद की टीम प्रथम, कुरुक्षेत्र दूसरे व कैथल तीसरे स्थान पर रही।

हरियाणा का गौरव बढ़ाएंगे खिलाड़ीः सीएम

करनाल के कर्ण स्टेडियम में 'खेलो हरियाणा' प्रतियोगिता के दूसरे दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा एकमात्र राज्य है जहां खिलाड़ी को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने पर छह करोड़ रुपए दिए जाते हैं। प्रदेश का खिलाड़ी विश्व में अपनी पहचान बनाए इसके लिए हरियाणा सरकार ने स्टेडियमों के प्रबंधन के लिए संरचनात्मक ढांचा तैयार किया है। उन्होंने स्टेडियम में बैठकर बॉक्सिंग व फुटबॉल का मैच देखा और बॉक्सिंग के खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया।

-संवाद ब्यूरो

बागवानी फसलों की बिक्री व उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 1000 किसान उत्पादक समूह बनाए जाएंगे। 600 किसान उत्पादक समूह बनाए जा चुके हैं। इन समूहों द्वारा 150 इंटीग्रेटेड पेक हाउस बनाए जाने हैं।

हरियाणा के भूमि पंजीकरण से संबंधित 7-ए नियम में संशोधन के अभूतपूर्व लाभ दिखाई देने लगे हैं। डीड-रजिस्ट्रेशन से स्टांप ड्यूटी में चालू वित्त वर्ष के दौरान अगस्त तक 2,692 करोड़ रुपए सरकारी खज़ाने में जमा हुए है

2500 दिन विकास के पथ पर राज्य सरकार

विशेष प्रतिनिधि

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार ने अपने 2500 दिनों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार मुक्त, पेपरलैस और फेसलेस शासन के एक नए युग की शुरुआत करने तथा जातिवाद, क्षेत्रवाद और जिलेवार भेदभाव से ऊपर उठते हुए हरियाणा के विकास की एक नई इबारत लिखी है। किसानों के हित के लिए कल्याणकारी योजनाओं से लेकर अंत्योदय की भावना से गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करके, युवाओं के लिए पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करके और आधारभूत संरचना पर जोर देते हुए हरियाणा के समग्र विकास को सुनिश्चित किया है। अब राज्य सरकार ऐसी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसमें ईज ऑफ लिविंग की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ते हुए प्रदेशवासियों के आर्थिक उत्थान के साथ-साथ हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने पिछले 2500 दिनों में जिस तरह के विकास कार्य, अपनी तरह की नई पहल, लोगों के कल्याण के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत करने से लेकर भविष्य का रोड मैप तैयार करने जैसे कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, तब से 2500 दिनों में राज्य सरकार सबका साथ - सबका विकास -सबका विश्वास-सबका प्रयास और हरियाणा एक-हरियाणवी एक के मंत्र पर चलते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के समान विकास को सुनिश्चित करते हुए हरियाणा को विकास पथ पर तेज़ी से ले जाने के लिए समर्पित रूप से काम कर रही है।

- किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न पहल और योजनाएं शुरू की गई हैं और इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत 2500 दिनों में लगभग 50 लाख किसानों के खातों में 11,000 करोड़ रुपए सीधे हस्तांतरित किए गए हैं।
- राज्य सरकार ने कृषि भूमि के आदान-प्रदान में किसानों को राहत प्रदान करते हुए स्टाम्प शुल्क में छूट दी गई है। अब प्रति डीड केवल 5,000 रुपए का शुल्क ही लिया जाएगा। पहले इस पर 7 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लगता था।
- फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री बगवानी बीमा योजना और बाज़ार में फसल के कम दाम होने पर उसकी भरपाई के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई है।
- फसल विविधीकरण के तहत धान की फसल के स्थान पर वैकल्पिक फसल की बुवाई के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत फसल विविधिकरण अपनाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

ढांचागत सुधार

- 17 नए राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए गए, इनमें से 11 पर कार्य प्रगति पर है।
- लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत से सराय काले खां-पानीपत के बीच रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कनेक्टिविटी की परियोजना बनाई गई है।
- लगभग 6,000 करोड़ की लागत से पलवल-सोनीपत और सोहना-मानेसर के लिए हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर स्वीकृत किया गया है।
- सोनीपत के बड़ी में 161 एकड़ भूमि पर रेल कोच रिपेयर फैक्टरी स्थापित की जा रही है।
- हिसार हवाई अड्डे को विकसित करने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।
- करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और हरियाणा में और भी नए स्मार्ट सिटी विकसित किए जाएंगे।

युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरी

- राज्य सरकार के कार्यकाल में 82,000 से अधिक युवाओं को मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है।
- पेपर लीक या नकल के दोषी दो साल तक भर्ती परीक्षा से वंचित करने, दो से दस साल तक की सजा और पांच हजार से दस लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है। इसके लिए हरियाणा लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक, 2021 पारित करवाया गया है।
- युवाओं को सरकारी नौकरी के लिए बार-बार आवेदन न करना पड़े, इसके लिए एकल पंजीकरण सुविधा शुरू की गई है। बार-बार परीक्षा व समय की बचत के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा का प्रावधान किया है।
- प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए निजी क्षेत्र के उद्यमों में उन्हें 75 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
- युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर देने के लिए प्रदेश में 2,000 हर हित स्टोर खोले जाएंगे। इनके अलावा 1,718 पैट्रोल पंपों पर भी ये स्टोर खोले जाएंगे।

अंत्योदय

- अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने के लिए श्रमिकों, गरीबों और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग से संबंधित लोगों, महिलाओं तथा बुजुर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
- ऐसे परिवारों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है।
- इसके प्रथम चरण में सबसे गरीब 2 लाख परिवारों की पहचान करके उनकी न्यूनतम वार्षिक आय एक लाख रुपए करने का लक्ष्य है।
- अब तक 48,000 परिवारों की पहचान की जा चुकी है, हमारा लक्ष्य ऐसे प्रत्येक परिवार की वार्षिक आय कम से कम 1.80 लाख रुपए करने का लक्ष्य रखा है।
- बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय सीमा 1.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए कर दी गई है, ताकि अधिक से अधिक परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- राज्य में सभी कोविड-19 रोगियों का इलाज और टीकाकरण निःशुल्क किया जा रहा है।
- बीपीएल परिवारों के कोरोना मरीजों का निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज किया गया।
- होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

सरकारी बसों में मिलेगी ई-टिकट

हरियाणा राज्य परिवहन सेवा की सभी बसों में ई टिकट की सुविधा शुरू होने जा रही है। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और रोडवेज के सिस्टम को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार जल्द ई-टिकटिंग सुविधा शुरू करने जा रही है। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजित हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में 4500 ई-टिकटिंग मशीन खरीदने का फैसला लिया गया है। इसके अंतर्गत सभी 24 डिपो कवर किए जाएंगे। इस योजना को छह महीने में लागू कर दिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने बताया कि ई-टिकटिंग शुरू होने से रोडवेज बसों में फ्री पास और रियायती कोटे के तहत यात्रा करने वाली सवारियों को एक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जारी किया जाएगा। इस कार्ड को जैसे ही कंडक्टर अपने ई-टिकटिंग कियोस्क पर स्कैन करेगा, उस यात्री की यात्रा से संबंधित डाटा कंट्रोल रूम में आ जाएगा। इससे विभाग को यह जानकारी रहेगी कि फ्री पास और रियायती कोटे के तहत कितने यात्रियों ने यात्रा की है।

रूटीन में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी एनसीएमसी कार्ड जारी किया जाएगा। इससे वे यात्री उस कार्ड में पहले से रिचार्ज करा सकते हैं और यात्रा के दौरान महज कार्ड को स्कैन करने से उनकी यात्रा का किराया कट जाएगा। इससे वे कैशलैश सुविधा से ई-टिकटिंग का लाभ ले सकते हैं।

हिंदी दिवस पर विशेष

मीरा केशव जायसी, हिंदी की जागीर।
देखी न्यारी गायकी, गुरु रैदास कबीर।
गुरु रैदास कबीर, सूर तुलसी से आला।
जयशंकर प्रसाद, शान बढाई निराला।
प्रेमचंद की शान, महादेवी की पीरा।
बच्चन और रहीम, शान हिंदी की मीरा।
हिंदी भाषा हिन्द की, प्यारी सी पहचान।
लिपि देवनागरी बनी, आन बान व शान।
आन बान व शान, मान देश का बढाये।
इसके सुंदर भाव, देश को एक बनाये।
भारत का अभिमान, लगे माथे की बिंदी।
बना मान सम्मान, देश की भाषा हिंदी।
बोह्ली बड़े कमाल की, बोह्ली कोनी घाट।
गजबण इसकी रागनी, हरियाणा के ठाठ।
हरियाणा के ठाठ, माट म्ह राखै पाणी।
बेशक कहैं लठमार, रसीह्ली म्हारी बाणी।

- भूपसिंह भारती, नारनौल

हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने अपने राजस्व में बढ़ोतरी के रिकार्ड को कायम रखते हुए फिर से 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। आबकारी विभाग को जहां नई आबकारी नीति का खूब लाभ मिला है।

'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' योजना जटिल भर्ती प्रक्रिया में बार-बार फीस भरने पर युवाओं को होने वाली आर्थिक परेशानियों से निजात मिलेगी। यह योजना शुरू होने से कर्मचारी चयन आयोग को भी काफ़ी राहत मिली है।

लाख चौरासी जीया जून मैं नाचै दुनिया सारी

लोक साहित्य में हरियाणे का खज़ाना कई सदियों से लबालब है। रागनी और सांग हरियाणवी लोक साहित्य की रीढ़ हैं। सांग तो यहां की लोकप्रिय नाट्य-शैली रहा है। यह विधा हरियाणा के लोकमानस पर जादू का-सा प्रभाव डालती है। रागनियों की स्वर-लहरी तथा वाद्य-संगीत से परिपूर्ण कथा को सुनकर व देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।

हरियाणा में सांग की प्राचीन परंपरा का विद्वानों ने वर्गीकरण समयानुसार हुए परिवर्तनों के आधार पर किया है। 1658 ईस्वी में औरंगज़ेब ने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया। 1707 ईस्वी औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात बालमुकुंद ने 1709 ईस्वी में सांग को पुनः जीवित करने का प्रयास किया। उनके देहावसान के बाद उनके शिष्य शिवकुमार ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। उनके दूसरे शिष्य किशनलाल भाट ने सांग-कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। किशनलाल भाट को 'सांग का पितामह' भी कहा जाता है।

हरियाणवी सांग-परंपरा के दूसरे चरण को प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है । इसका समय 1750 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक है । इस युग के सांगियों में सर्वप्रथम नूह ज़िले में जन्में सादुल्ला का नाम आता है । उन्हें मेवाती जनकवि होने का गौरव प्राप्त है उन्होंने 1787 ईस्वी में मेवाती भाषा में महाभारत की रचना की है जिसका नाम 'पण्डून का कड़ा' है।

हरियाणवी सांग परंपरा के 1850 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक के तीसरे युग को सांग-साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस युग का प्रारंभिक दौर भक्ति भावना से ओतप्रोत रहा। इस युग में अनेक प्रसिद्ध सांगी हुए जिनमें अलीबख्श, बालकराम, अहमदबख्श थानेसरी, बाबा हीरादास उदासी, ताऊ सांगी, पंडित किशन लाल, दीपचंद, बाजे भगत, पंडित लखमीचंद आदि।

अलीबख्श रेवाड़ी के क्षेत्र में लोकप्रिय थे। इनके सांगों में भक्ति-भावना प्रमुख थी। इनके सभी सांग ईश्वर-वंदना से आरंभ होते थे । इनके प्रमुख सांगों में श्री कृष्ण लीला, गुलबकावली, फिसाने अजाइब आदि का नाम लिया जा सकता है ।

योगेश्वर बालकराम शेखपुरा गांव; जिला करनाल के निवासी थे। इन्होंने 'पूरणमल भगत' तथा 'निहालदे नर सुल्तान' जैसे सांगों की रचना की । इनके शिष्य पंडित रामकिशन ब्यास भी प्रसिद्ध सांगी हुए।

अहमदबख्श थानेसरी ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। इनकी रचनाओं में ज्योतिष शास्त्र, हिंदू-मुस्लिम संस्कृति का समन्वय तथा वात्सल्य भाव आदि का अनूठा मिश्रण मिलता है । सोरठा, पद्मिनी, चंद्रकिरण, कृष्ण लीला आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ।

ताऊ सांगी भी हरियाणा के विख्यात सांगी हुए हैं । इन्होंने 'रुक्मणी विवाह' नामक पद्यबद्ध सांग की रचना की जिसमें 178 पद्य हैं । पंडित किशनलाल ने मोरध्वज, भक्त प्रह्लाद, बारहमासा आदि सांगों की रचना की। पंडित दीपचंद ने हरियाणवी सांग को नई प्रतिष्ठा प्रदान की। इन्होंने नल-दमयंती, राजा भोज, गोपीचंद आदि सांगों की रचना की। बाजेराम भी हरियाणा के लोकप्रिय सांगी हुए हैं। नल-दमयंती, हीर-रांझा, महाभारत आदि पर्व, कृष्ण-जन्म आदि इनके प्रमुख सांग हैं।

पंडित लखमीचंद को हरियाणवी लोक साहित्य के युग पुरुष की संज्ञा दी जाती है। वे सर्वाधिक प्रतिभावान सांगी थे। उन्होंने सांगों को दैनिक जीवन से जोड़ा तथा रागनी के वर्तमान रूप को जन्म दिया। पूरणमल, गोपीचंद, शकुंतला, हीर-रांझा, पद्मावत, चंद्रहास आदि उनके प्रमुख सांग हैं ।

हरियाणवी सांग-परंपरा का चौथा चरण यानी(1950 ईस्वी से अब तक) आधुनिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल की समय-सीमा 1950 से लेकर अब तक मानी जाती है। इस युग के सांगियों में पंडित मांगेराम, रामकिशन व्यास, धनपत सिंह, फौजी मेहर सिंह आदि का नाम उल्लेखनीय है।

पंडित मांगेराम पंडित लखमीचंद के शिष्य थे इन्होंने लगभग 40 सांगों की रचना की। इनके सांगों में छैल बाला, अमर सिंह राठौर, पिंगला भरथरी, कृष्ण-सुदामा आदि प्रमुख हैं । रामकिशन ब्यास प्रसिद्ध सांगी योगेश्वर बालक राम के शिष्य हुए हैं। इनके प्रमुख सांग हैं- सत्यवान सावित्री, चंद्रहास, शशिकला आदि। धनपत सिंह पंडित मांगेराम के समकालीन थे। हीर-रांझा, लीलो चमन, गोपीचंद आदि इनके प्रमुख सांग हैं।

हरियाणवी लोक साहित्य में फौजी मेहर सिंह का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वह पंडित लख्मीचंद के शिष्य थे। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में कार्य किया था। सत्यवान सावित्री, सरवर नीर, शाही लकड़हारा, सुभाषचंद्र बोस आदि उनकी प्रमुख रचनाएं है ।

- सुरेंद्र बांसल

दादा लख्मी की एक प्रसिद्ध रागनी

लाख चौरासी जीया जून मैं नाचै दुनिया सारी
नाचण मैं के दोष बता या अकल की हुशियारी
सब तै पहलम विष्णु नाच्या पृथ्वी ऊपर आकै
फिर दूजे भस्मासुर नाच्या सारा नाच नचा कै
गौरां आगै शिवजी नाच्या ल्या पार्वती नै ब्याह कै
जल के ऊपर ब्रह्मा नाच्या कमल फूल के म्हा कै
ब्रह्मा जी नै नाच-नाच कै रची सृष्टि सारी।
गोपनियां मैं कृष्ण नाच्या करकै भेष जनाना
विराट देश मैं अर्जुन नाच्या करया नाचना गाणा
इन्द्रपुरी मैं इन्द्र नाचै जब हो मींह बरसाणा
गढ माण्डव मैं मलके नाच्या करया नटां का बाणा
मलके नै भी नाच-नाच कै ब्याहल्यी राजदुलारी
पवन चलै जब दरख्त नाचैं पेड़ पात हालैं सैं
लोरी दे-दे माता नाचैं बच्चे नै पाळैं सैं
रण के म्हां तलवार नाचती किसे हाथ चालैं सैं
सिर के ऊपर काळ नाचता नहीं घाट घालै सै
काल बली नै नाच खा लिए ऋषि-मुनि-ब्रह्मचारी।
बण मैं केहरी शेर नाचता और नाचे सै हाथी
रीछ और बंदर दोनों नाचैं खोल दिखावैं छाती
गितवाड़े मैं मोर नाचता कैसी फांख फरांती
ब्याह शादी मैं घोड़ी नाचैं जिस पै सजैं बराती
दूर दराज कबूतर नाचैं लगैं घुटरगूं प्यारी।
दीपचन्द खाण्डे मैं नाच्या सदाव्रत खुलवाग्या
बाजे नाई नाच-नाच कै और भी भक्त कुहाग्या
हावळी मैं नत्थू ब्राह्मण मन्दिर नया चिणाग्या
'लखमीचन्द' भी नाच-नाच कै नाम जगत मैं पाग्या
इसे-इसे भी नाच लिए तै कौण हकीकत म्हारी।

सुण छबीले बोल रसीले

काम तो करणा पड़ैगा

छबीला- रसीले, के बात होई, क्यूकर लंगड़ाता चालै सै?

-छबीले के बताऊं, आंदोलन में गया था। उड़ै केले के पापड़ पर तै पां रिपटग्या और कूल्ही जा लागी। इब ताहीं दर्द सै। शूकर सै फैक्चर कोन्या होया।

- उड़ै के डोक्के लेण गया था? बामण नै बता राखी थी, अक उड़ै जाइये। ले ईब जी-से ।

-अरै वो भगता भका लेग्या। बोल्या, आज्या चालैंगे, सारे दिन आड़ै ताश ए ना पीटैगा। उड़ै खाण-पीण की कोए दिक्कत नां। सांझ ताहीं उल्टे आ लेंगे। चल्या गया। पर के मिलणा था। बिरानमाटी में साझा था।

-तेरै धौरै एक किलड़ी सै। बोल चपाका उसमैं बोएं जा और खाएं जा। टैम पै बीज मिलै, खाद मिलै, पाणी मिलै और मंडी में भाव बढ़िया मिलै। भगवान ना करै फसल खराब होज्या तै मुआवजा मिलै। और के चाहिए? सरकार के उसमैं डॉलर बुआवैगी?

सारा दिन तो ताश पीटैं सैं। खेत में जाकै झांकते नहीं। चाहवै न्यूं अक सरकार ए खेत में काम करै और सीधे खात्यां में नोट भरै। बिना करे खाण नै कितौड़ तैं आवैगा भाई? असल बात यो सै अक माणसां कै ठाल लाग गी।

रसीले तनै एक बात देखी। धान लाणे हों जिब पूरबिए, काटणे हों जिब पूरबिए। ईंख नुलाणा हो या काटणा हो जिब बाहर के मजदूर खेतां में काम करैं सैं। गेहूं की कटाई मशीनां गेल हो सै। और तो और लोगां नै डांगर ढोर का काम करण खातिर भी बाहर के मजदूर ला राखे सैं।

-हां भाई छबीले, बेरा ना के बिजली पड़ैगी। कोई काम करकै राजी कोन्या। गाम में कितोड़ चिनाई लागरी हो सै तो उड़ै भी बाहर के मजदूर ए काम करते दिखाई दे सैं।

-फेर न्यू कहैं सैं, अक बेरोजगारी बढ़गी।

-भाई पढणिए बालकां नै तो कोई दिक्कत कोन्या। वे कितो न कितो कामयाब होज्या सैं। बिना पढणिया तो फेर कुछ भी कहो। मुंह आगै मैदान पड़्या सै।

-छबीले, पढ़ाई लिखाई बिना आजकाल रिश्ते भी ना होते। आच्छे-बिच्चे बालक भी कुअरे हांडैं सैं।

-रसीले, मेरे मामा का छोरा सै, 30-32 साल का। ना पढ़्या और ना कुछ काम-धाम। चाहवै न्यू अक बढ़िया रिश्ता आज्या। कोन्या आया। बाट देखकै पड़ौसी प्रदेश मं तै बहू ले आया। मंदिर में ब्याह करा लिया। छोरी आलैं तै दो लाख रपयै दिए और दूसरा खर्चा होया, वो अलग। कुल मिलाकै अढ़ाई-तीन लाख खर्चं होगे।

-फेर के होया?

-फेर वोए होया जो होणा था। भाजगी। बहू घरां आई थी। तीन दिन पाछै एक जनानी और दो माणस आए और बोले हाम बहू के पीहर तैं आए सैं। एक हफ्ते की कहै कै उसनै लेगे। दो म्हीने होगे, फोन बंद, बहू का कोई अता-पता नहीं।

-भाई छबीले, तेरे उस भाई का ब्याह बिना जी सुकै था? उसतैं बिना बहू सुख तैं नहीं रहा गया? ईब उस भाई का एचआईवी टेस्ट भी करा लियो। कदे ना कतई धरती कै भिड़ागी हो।

-हां भाई, मनै तो गड़बड़ लागै सै। अरै रसीले, उसनै ब्याह तैं पहल्यां मेरे आगै जिक्रा कोन्या कर्‌या, नहीं तो मैं यू रिश्ता ना होण दयूं हैं। पर मेरा बटा, कुल्हड़ी में गुड़ फोड़ै था। ईब के कर्‌या जा सकै सै?

- छबीले एक काम कर्‌या जा सकै सै। ईब उसकी रांडेपने की पिल्सण बणवा द्यो।

-बावळा सै तूं। बहू भाजगी तो रांडा क्यूकर होया?

-पूछताछ करण मं के जा सै। कोशिश तो करो। सरकार नै निरां की पिल्सण बणा राखी सै। के बेरा इसका भी तुक्का लागज्या।

-भाई रसीले, पिल्सण तैं काम कोन्या चालै। जूनी में आए सैं तो काम करणा पड़ैगा। काम करे बिना खाण नै कितोड़ तैं भी कोन्या आवै। ना करणिए माणस की बुढापे मं रे रे माटी होया करै। बुढापे में बाळक साथ ना दें तो जेबखर्ची तैं टैम कटज्याया करै।

पर तूं घणे स्वाद ना ले, जा होक्का भरल्या।

-मनोज प्रभाकर

डॉ अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. प्रबंध निदेशक, संवाद (सूचना जन संपर्क एवं भाषा विभाग) हरियाणा द्वारा हरियाणा सरकार के लिए कमरा नं. 314, दूसरी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला से प्रकाशित।
कार्यालय : संवाद सोसायटी एससीओ 23, पहली मंजिल, सेक्टर 7, चंडीगढ़ फोन : 0172-2723814, 2723812 email : editorsamvad@gmail.com